1

न्यायमूर्ति एच.एस. राय और ए.पी. चौधरी, जे.जे. के समक्ष

सुनील कुमार सभरवाल,-याचिकाकर्ता,

बनाम

श्रीमती नीलम सभरवाल और अन्य-प्रतिवादी।

आपराधिक विविध. 1990 का क्रमांक 5809-एम.

1 नवंबर, 1990.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973– धारा 125, 397(2) और 482-पत्नी और नाबालिग बच्चे को अंतरिम भरण-पोषण देने का आदेश-क्या इसे अंतरिम आदेश कहा जा सकता है-ऐसे आदेश के खिलाफ संशोधन-क्या वर्जित है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 397(2) के तहत अभिव्यक्ति 'इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर' को एक प्रतिबंधित अर्थ दिया जाना है। वे आदेश जो पूरी तरह से प्रक्रियात्मक हैं, मामले की प्रगति के लिए आवश्यक हैं, जैसे गवाहों को बुलाने, मामलों को स्थगित करने आदि के आदेश अंतर्वर्ती हैं। मामले का अंत होना किसी आदेश को अंतर्वर्ती आदेश की श्रेणी से बाहर करने के लिए अनिवार्य नहीं है। महत्वपूर्ण परीक्षण यह है कि आदेश पूरे मामले या उसके किसी भी पहलू के संबंध में पार्टियों के अधिकारों और देनदारियों को काफी हद तक प्रभावित करता है। उपरोक्त परीक्षणों को लागू करते हुए, हमारा मानना है कि विचाराधीन आदेश, एक अंतर्वर्ती आदेश नहीं है। आदेश के तहत याचिकाकर्ता पर भरण-पोषण का भुगतान करने का दायित्व डाला गया था। यह या तो अंतिम रूप से निर्णय लिया गया था या इसमें परिवर्तन किया गया था। राशि के भुगतान में चूक होने पर याचिकाकर्ता के खिलाफ उत्पीड़नात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया

जा सकता है। यह स्पष्ट है कि पार्टियों के अधिकार और (1992) 1
देनदारियां आक्षेपित आदेश द्वारा मामले के अंतिम निर्णय तक निर्धारित थीं और इसलिए, आदेश को अंतरिम नहीं माना जा सकता था। यह तर्कसंगत नहीं है कि पीड़ित पक्ष के पास अंतरिम भरण-पोषण तय करने वाले आदेश के खिलाफ कोई उपाय नहीं होना चाहिए।

(पैरा 7)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि अंतरिम भरण-पोषण देने वाला आदेश एक अंतरिम आदेश नहीं है और संहिता की धारा 397(2) के तहत इसके खिलाफ संशोधन वर्जित नहीं है। (पैरा 9)

याचिकाकर्ता के वकील सी. बी. गोयल।

प्रतिवादियों की ओर से एच.एस. गिल, वकील।

न्याय

न्यायाधीश ए पी चौधरी

(1) हमारे विचार के लिए संक्षिप्त और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या कार्यवाही में अंतरिम भरण-पोषण देने का आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 (इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित) संहिता की धारा 397 (2) के अर्थ के भीतर एक अंतर्वर्ती आदेश है ताकि संशोधन पर रोक लगाई जा सके।

(2) 'तथ्यात्मक आधार देने के लिए' केवल कुछ तथ्यों को बताने की आवश्यकता है। भरण-पोषण के लिए एक याचिका के लंबित रहने के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ ने 24 जनवरी 1990 के आदेश द्वारा रुपये की दर से अंतरिम भरण-पोषण प्रदान किया। प्रतिवादी नंबर 1 (पत्नी) को 500 प्रति माह और रु. प्रतिवादी नंबर 2 (नाबालिग बेटे) को 800 रुपये प्रति माह। याचिकाकर्ता की पुनरीक्षण याचिका को

विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ ने 28 अप्रैल, 1990 के आदेश द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अंतरिम भरण-पोषण का आदेश अंतिम आदेश नहीं था और यह केवल एक अंतरिम आदेश था और इस तरह का पुनरीक्षण सुनवाई योग्य नहीं था। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पवन कुमार बनाम चंचल कुमारी (1), और हरजीत सिंह बनाम जसजीत कौर (2) में इस न्यायालय के दो एकल पीठ निर्णयों का पालन किया। आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने नीचे के दोनों न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने के लिए संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय में वर्तमान याचिका दायर की। याचिका पर हमारे विद्वान भाई जे.एस. सेखों जे. ने सुनवाई की। उन्होंने ऊपर उद्धृत दो निर्णयों के साथ-साथ सुमेर चंद बनाम संधुरन रानी और अन्य (3) में इस न्यायालय के एक अन्य एकल पीठ के फैसले में विचारों का विरोधाभास देखा। प्रश्न के महत्व को देखते हुए उन्होंने याचिका को बड़ी पीठ के समक्ष स्वीकार कर लिया। इस तरह हमने याचिका पर सुनवाई की है ।

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क यह है कि आक्षेपित आदेश ने याचिकाकर्ता पर काफी वित्तीय दायित्व का बोझ डाल दिया है। यदि याचिकाकर्ता इसका अनुपालन करने में विफल रहा, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और जेल भेजा जा सकता है। यह आदेश आम तौर पर मुख्य याचिका के अंतिम निर्णय तक लागू रहेगा, जिसमें काफी समय लग सकता है, यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि पुनरीक्षण को रोक दिया जाता है, तो पीड़ित व्यक्ति के पास एकमात्र उपाय उच्च न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार संहिता की धारा 482 ऐसी कार्रवाई में शामिल सभी कठिनाइयों के साथ लागू करना है।

(4) दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील श्री एच.एस. गिल का तर्क है कि विचाराधीन आदेश केवल पार्टियों के नेतृत्व में दिया गया आदेश है। वकील ने प्रस्तुत किया कि

आदेश से जुड़ी अंतिमता के अभाव में, यह केवल एक अंतरिम आदेश था और संहिता की धारा 397 (2) में निहित विधायी नीति एक अंतरिम आदेश के खिलाफ संशोधन पर रोक लगाती है। उनके अनुसार, इसलिए, विवादित आदेश असाधारण था और संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार को लागू करने का कोई मामला नहीं था।

(5) हमने पक्षों के विद्वान वकील की संबंधित दलीलों पर उत्सुकतापूर्वक विचार किया है।

(6) संहिता में 'अंतर्वर्ती आदेश' शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। हालाँकि, उक्त अभिव्यक्ति की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमर नाथ बनाम हरियाणा राज्य (4) में पहली बार इन शब्दों में की थी: -

निर्णयित मामलों में यह निर्धारित किया गया है कि लागू होने वाले अंतर्वर्ती आदेश वे होने चाहिए जो किसी विशेष पहलू से संबंधित पक्षों के अधिकारों और दायित्वों का निर्णय करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि 1973 संहिता की धारा 397 (2) में अंतर्वर्ती आदेश शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग किसी व्यापक या कलात्मक अर्थ में नहीं बल्कि प्रतिबंधित अर्थ में किया जाता है। यह केवल विशुद्ध रूप से अंतरिम या अस्थायी प्रकृति के आदेशों को दर्शाता है जो पार्टियों के महत्वपूर्ण अधिकारों या देनदारियों पर निर्णय या स्पर्श नहीं करते हैं। कोई भी आदेश जो अभियुक्तों के अधिकारों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, या पार्टियों के कुछ अधिकारों का निर्णय करता है, उसे एक अंतरिम आदेश नहीं कहा जा सकता है ताकि उस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण पर रोक लगाई जा सके, क्योंकि यह उसी उद्देश्य के विरुद्ध होगा जो 1973 की संहिता की धारा 397 में इस विशेष प्रावधान को शामिल करने के लिए आधार

बनाता है।इस प्रकार, उदाहरण के लिए, गवाहों को बुलाने का आदेश, मामलों को स्थगित करने, जमानत के लिए आदेश पारित करने, रिपोर्ट मांगने और लंबित कार्यवाही की सहायता के लिए ऐसे अन्य कदम निस्संदेह अंतरिम आदेशों के समान हो सकते हैं जिनके खिलाफ 1973 की संहिता की धारा 397 (2) के तहत कोई संशोधन नहीं होगा। लेकिन वे आदेश जो क्षणिक मामले हैं और जो अभियुक्त के अधिकारों या मुकदमे के किसी विशेष पहलू को प्रभावित करते हैं या निर्णय देते हैं, उन्हें अंतरिम आदेश नहीं कहा जा सकता है ताकि वे उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के दायरे से बाहर हों।

(7) मधु लमाये बनाम महाराष्ट्र राज्य (5) में भी इसी व्याख्या को मंजूरी दी गई थी और इसकी पुष्टि की गई थी। हसमुख जे. झवेरी बनाम शीला ददलानी और एक अन्य *(6) मामले में* बॉम्बे *उच्च न्यायालय के एक* विद्वान न्यायाधीश ने मामले के कानून की समीक्षा की और 12 प्रस्तावों के रूप में सार को कम कर दिया।संक्षेप में, इसे स्थापित कानून के रूप में लिया जा सकता है कि संहिता की धारा 397 (2) * के तहत 'अंतर्वर्ती आदेश' अभिव्यक्ति को एक प्रतिबंधित अर्थ दिया जाना है।ऐसे आदेश जो विशुद्ध रूप से प्रक्रियात्मक हैं, मामले की प्रगति के लिए आवश्यक हैं, जैसे कि गवाहों को बुलाने के आदेश, *मामलों को स्थगित* करने आदि के आदेश अंतर्वर्ती हैं। मामले का अंत होना किसी आदेश को अंतर्वर्ती आदेश की श्रेणी से बाहर किए जाने की अनिवार्य शर्त नहीं है। महत्वपूर्ण परीक्षा यह है कि आदेश समग्र रूप से मामले या उसके किसी भी पहलू के संबंध में पक्षों के अधिकारों और देनदारियों को काफी हद तक प्रभावित करता है।उपरोक्त परीक्षणों को लागू करते हुए, हमारा मानना है कि विचाराधीन आदेश, एक अंतर्वर्ती आदेश नहीं है। आदेश के तहत याचिकाकर्ता पर तब तक भरण-पोषण का भुगतान करने का दायित्व डाला गया जब तक कि इस पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता या इसमें बदलाव नहीं हो जाता। राशि के भुगतान में चूक होने पर, याचिकाकर्ता के

खिलाफ दंडात्मक प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है।यह स्पष्ट है कि पक्षकारों के अधिकार और देनदारियाँ विवादित आदेश द्वारा मामले के अंतिम निर्णय तक निर्धारित की गई थीं और इसलिए आदेश को अंतरिम नहीं माना जा सकता था। यह तर्कसंगत नहीं है कि है कि पीड़ित पक्ष के पास अंतरिम भरण-पोषण तय करने के आदेश के खिलाफ कोई उपाय नहीं होना चाहिए।

(8) यही प्रश्न सीधे तौर पर सुमेर चंद बनाम संधूरन रानी और अन्य (सुप्रा) मामले में उठा। न्यायमूर्ति उजागर सिंह, द्वारा इसकी कुछ विस्तार से जांच की गई और यह अभिनिर्धारित किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अंतरिम भरण-पोषण देने वाला आदेश एक अंतरिम आदेश नहीं था। दूसरी ओर, हरजीत सिंह बनाम जसजीत कौर (7) में एक विपरीत विचार व्यक्त किया गया था। विद्वान न्यायाधीश ने टेक चंद बनाम नरैनी देवी और अन्य (8), और पवन कुमार बनाम चंचाई कुमारी (9) में पहले के दो एकल पीठ के फैसलों का पालन करने का इरादा किया। ये दोनों आदेश संक्षिप्त हैं और जो अभिनिर्धारित किया गया था वह यह था कि इन मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों में संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार को लागू नहीं किया जा सकता है।

(9) ऊपर बताए गए कारणों से, हम मानते हैं कि अंतरिम भरण-पोषण देने वाला आदेश एक अंतरिम आदेश नहीं है, और उसके विरुद्ध संशोधन संहिता की धारा 397(2) के तहत वर्जित नहीं है। इसलिए, हम विद्वान अतिरिक्त आयुक्त द्वारा 28 अप्रैल 1990 को पारित के आदेश को रद्द करते हैं और रद्द करते हैं। सत्र न्यायाधीश और निर्देश देते हैं कि वह वर्तमान पुनरीक्षण याचिका को उसके मूल क्रमांक के विरुद्ध दर्ज करेंगे और तीन महीने की अवधि के भीतर कानून के

अनुसार गुण-दोष के आधार पर सुनवाई करेंगे और उसका निपटारा करेंगे। पक्षों को अपने वकील के माध्यम से 3 दिसंबर, 1990 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ की अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

पी.सी.जी.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

कोमल दहिया

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा